की जा रही है, और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

1298. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित किराया नियंत्रण अधिनियम में ऐसे व्यवसायिक भवनों को, जो कि अनेक वर्षों से बहुत कम किराये पर व्यावसायिक घरानों के कब्जे में है, उन्हें खाली कराने या उनका किराया वर्तमान दर पर लाने के लिये कोई उपबंध न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) ऐसे मामलों में इन व्यापारिक दुकानों के संबंध में तथा फ्लैट मालिकों को राहत दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक परिसरों के संबंध में दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 के विद्यमान प्रावधानों को पर्याप्त समझा गया है तथा इस प्रकार, वाणिज्यिक भवनों को खाली करवाने के लिये संशोधी विधेयक में विशिष्ट प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है । इसी प्रकार से अधिनियम की धारा 6 और 7 में उल्लिखित प्रावधानों को जहां तक मानक किराये का संबंध है, उपयुक्त पाया गया । तथापि, किसी परिसर के संबंध में प्रत्येक तीन वर्षों में किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये एक नये प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है । इससे भवन के रखरखाव की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति करके मकान मालिकों को राहत मिलेगी ।

पम्प सैटों और ट्रैक्टरों के मूल्य

1299. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को विभिन्न प्राधिकृत एजेंसियों/कम्पनियों से ट्रैक्टर और पम्प की खरीद करने पर खुले बाजार की तुलना मे अधिक धन व्यय करना पड़ता है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा किन-किन कम्पनियो/एजेंसियों को प्राधिकृत किया गया है ; और

(ग) विभिन्न श्रेणी के पम्प सैटों और ट्रैक्टरों के खुले बाजार में तथा सरकार द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों के अलग-अलग मूल्य क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) ट्रैक्टरों और पम्प सैटों की बिक्री पर कोई मूल्य नियंत्रण नही है । ट्रैक्टरों और पम्प सैटों के मूल्य भिन्न-भिन्न होते हैं क्योंकि ये मूल्य अश्वशक्ति और उपकरणों की किस्म पर निर्भर होते हैं और ये एक निर्माता से दूसरे निर्माता के पास भिन्न-भिन्न किस्म के होते हैं । ट्रैक्टरों और पम्प सेटों की बिक्री निर्माताओं के डीलरों के माध्यम से की जाती है ।

(ख) सरकार ने पम्प सैटों और ट्रैक्टरों की बिक्री के लिये किसी भी कम्पनी को विशेष रूप से प्राधिकृत नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Employment for persons returning from Gulf countries

1300. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indians who are employed in Gulf countries are returning since their jobs were over in the Gulf States; and

(b) if so, what is the package scheme Government propose to implement for giving employment to them?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes, Sir.

The emigrants from the Gulf countries return once their period of contract is over.

(b) Government has not framed any package scheme for providing employment to returning emigrants.

Labours forced to join army in other country

1301. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the labour recruiting agencies in the country have been found violating the labour laws etc.;

(b) if so, the details of such agencies detected during the last one year;

(c) whether the most of the agencies after recruiting the labour are insisting to join army in other country instead of the actual work; and

(d) if so, what are the details in this regard and what action Government propose to contemplate in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) and (b) During 1987 registration certificates of six recruiting agencies were suspended and certificate of one agency cancelled for violation of the provisions of the Emigration Act, 1983;

(c) and (d) Government has received a complaint against only one Recruiting Agency who was indulging in the diversion of workers to Military Camps on arrival in the foreign country. A case has been registered against this recruiting agency by Delhi Police and three persons have been arrested. The Registration Certificate of the Recruiting Agency has been cancelled.

Publicity about BIS mark

1302. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Standards Institution (ISI) has since been ceased and is replaced by Bureau of Indian Standards (BIS);

(b) whether the consumers are still not aware of this modification and insist on ISI mark goods;

(c) whether in view of public interest, Government propose to aware the consumers to buy only BIS mark goods and the details of the more consumer item likely to be included in the list of BIS; and

(d) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) Yes, Sir.

(b) No Sir. The reason is that though the name of the organisation has changed from Indian Standards Institution to Bureau of Indian Standards, the standard mark continues to be based on the familiar monogram ISI.

(c) Since the establishment of the Bureau, through a number of programmes on Doordarshan and All India Radio, activities of the Bureau are highlighted and consumers are made aware of the advantages of buying only ISI mark goods.

(d) Some of the new consumer items proposed to be included into the fold of Compulsory ISI Certification are as follows:-

(i) Synthetic detergents;

(ii) Clinical thermometers;

(iii) Infant foods;

(iv) Rubber Tubing for connecting LPG Cylinder and Stove; and

(v) Sphygommanometers.

In considering these proposals, problems relating to implementation, preparatory steps especially by small scale and tiny units and socio-economic consideration have to be kept in view.

Incentives to Orissa fishing industry

1303. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what steps have been taken by Government to assist the Orissa fishing industry during the current year; and